to suitable professional and experienced caterers of good standing. At other stations these are normally licensed out to local professional men, including experienced displaced caterers or vendors settled in the area. Other things being equal, preference is given to displaced persons and registered Co-operative Societies, and as between these two categories, to the former. The ability to provide service of a high standard is of prime consideration in the award of these contracts.

(b) Auctioning of these contracts is not resorted to, either at stations or in the Head Office. The license fee is predetermined on the basis of vending prospects and the contracts are given on the basis of applications received, each such application being carefully scrutinised to ascertain the applicant's ability to perform the work satisfactorily.

(c) Applications are invited by advertisement in press in the case of more important contracts and by means of notices posted on station premises for the smaller contracts.

Shri Dhusiya: What are the more important contracts and how are they advertised—whether it is done in local papers, or in regional papers or in the office on the notice board?

Shri Shahnawaz Khan: The more important contracts are contracts at bigger stations like Howrah, Moghul-Sarai and places like Lucknow. The advertisements are given in the local papers as well as in papers of an All India nature.

Shri Dhusiya: My question was: what are the more important articles for which advertisement is made?

Shri Shahnawaz Khan: It is not a question of articles, it is a matter of important stations.

Kumari Annie Mascarene: May I know what percentage of the gain on contracts is given to the Government?

Shri Shahnawaz Khan: We do not work out the percentage of profits of the contractors. A certain licence fee is charged keeping in view the net profits of the contractors.

Shri Dhusiya: One question more.....

Mr. Speaker: We will go to the next question.

श्री भक्त दर्शन : प्रश्नकर्त्ता ने इस प्रश्न को पूछने का मुझे अधिकार दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सबसे बाद में लिया जायगा ।

चितरंजन में रेलवे इंजनों का कारखाना

*१०२१. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छै महीनों में चितरंजन के रेलवे इंजनों के कारखाने में काम की क्या प्रगति हुई है ?

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): Compared with a target production of 36 locomotives 46 have been completed between 1st April, 1954 to 30th September, 1954 and this outturn compares with a total production of 64 during the whole of 1953-54.

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो इंजन यहां पर तैयार किये जाते हैं, उनके जो पुर्जे होते हैं उनमें से कितने प्रतिशत बाहर से मंगाये जाते हैं ?

Shri Alagesan: Does he refer to imported items?

Mr. Speaker: Yes; whether it is 80 per cent., 85 per cent. or 90 per cent. and what is the percentage of indigenous manufacture?

Shri Alagesan: I may, say, Sir, that out of a total of 5,335 components as many as 4,475 are manufactured by Chittaranjan and another 769 are procured from indigenous manufacturers Only 90 items are imported from abroad.

Shri K. C. Sodhia: What is the percentage price of these 90 imported items?

Shri Alagesan: The percentage may be a little more than what the number of items represent. As it is, I am not able to give the actual percentage of cost; it is not much.

Shri T. S. A. Chettiar: How does the cost of engines compare as compared with the imported engines?

Shri Alagesan: As far as indigenous cost is concerned our price has now become almost equal to the imported price. If we increase the manufacture, it is bound to go down.

Shri T. B. Vittal Rao: May I know at what stage is the proposal to step up the production of this Chittaranjan Factory from 120 to 150? May I also know whether we are manufacturing at Chittaranjan only goods locomotives or passenger locomotives as well?

Shri Alagesan: Both locomotives are being manufactured and we are pursuing the question of increasing the production target.

रेलों पर भोजन व्यवस्था

*१०२४. **श्री एम० एन० सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों को, रेलों पर ठेकेदार और भोजन की व्यवस्था करने वाले भिन्न भिन्न स्थानों पर एक सा ही भोजन भिन्न भिन्न दरों पर देते हैं ?

(ख) क्या इन भोजनों के लिये कोई निर्धारित दरें हैं; और यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या भोजन की किस्म और मात्रा के सम्बन्ध में कोई विशेष निर्देश हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) उपाहार गृहों से दिये गये हिन्दुस्तानी ढंग के भोजन का स्तर १-६-५४ से एकसा कर दिया गया है । सदन में जो विवरण दिया गया है उसमें भोजन की सूची और उनके दाम दिये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६१] रेस्तोरां, रेस्तोरांयान, भोजन-यान या बुफे-यान से दिये जाने वाले भोजन की दर को एक स्तर पर लाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । कुछ मदों को छोड़ कर जिनका ब्यौरा और जिनकी किस्म सूची में दे दी जाती हैं, प्रामाणिक भोजन सूची में केवल परसी जाने वाली तश्तरियों के नाम दिये जाते हैं । भोजन की किस्म के बारे में कोई बात निर्धारित नहीं की गयी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की रुचि के अनुसार अच्छा भोजन देने की व्यवस्था जारी रखी जाय ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या संसद् सचिव को यह मालूम है कि एक ही कीमत पर विभिन्न स्टेशनों पर जो आप के ठेकेदार हैं वह ऐसा भोजन मुसाफिरों को देते हैं जो खाने के योग्य नहीं होता है और उनकी कीमत हर स्टेशन पर एक ही होती है जब कि भोजन में फर्क होता है और अगर ऐसी बात है तो इस को रोकने का कौन सा प्रबन्ध किया है ?

श्री शाहनवाज खां : हमें कभी कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि जो भोजन स्टेशनों पर मिलता है वह बहुत अच्छा नहीं होता है । जो जो शिकायत मिलती हैं उस पर गहरा विचार किया जाता है और मुनासिब कार्यवाही की जाती है । एक स्टैन्डर्ड मीनु बनाया गया है जिसमें करीब सारी रेलवेज पर एक ही कीमत पर एक ही किस्म का खाना देने का बन्दोबस्त किया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि जो अलगेशन कमिटी की सिफारिशें थीं वह कहां तक अमल में लाई गई ?

श्री शाहनवाज खां : अलगेशन कमिटी की जो सिफारिशात थीं वह इस वक्त आनरेबल मिनिस्टर के जेर गौर हैं ।